

प्रेषक,

जे. पी. जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक:-०८ अगस्त, 2012

विषय:-वित्तीय वर्ष 2012-2013 हेतु वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या: 2031/xx-1/12-5(4)/2012 दिनांक 27 जुलाई, 2012 के प्रस्तर 03 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना, रेडियो अधिष्ठान तथा अग्नि से संरक्षण एवं नियंत्रण अधिष्ठान हेतु वचनबद्ध एवं अवचनबद्ध मदों में आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-2013 में आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अधिष्ठान/मदवार कुल ₹ 66.4592 करोड़(रुपये छयासठ करोड़ पैंतालीस लाख बानब्बे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28 मार्च, 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि विभागवार पृथक अलोटमेंट आई.डी. (S1207100919 दिनांक 24.07.2012) के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन अवमुक्त कर दी गयी है। आवश्यक धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

3- वचनबद्ध मदों यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जलप्रभार, किराया, पेंशन, भोजन व्यय, मजदूरी आदि मदों की धनराशि के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्यय-भार सृजित किया जायेगा।

4- अधिष्ठान सम्बन्धी अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में

कमश: 2....

आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी तथा मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ से ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

5— पुलिस विभाग के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में विशेषकर अवचनबद्ध मदों में किसी मुद्रण(टंकक) त्रुटि के कारण बजट प्राविधान/आवंटन में वृद्धि हुयी हो, उन प्रकरणों के सम्बन्ध में धनराशि व्यय से पूर्व वस्तुस्थिति शासन के संज्ञान में लाते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

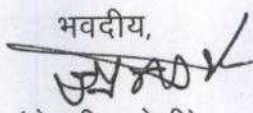
6— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7— अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का शासन की बिना सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है तथा पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा-151 के अन्तर्गत परीक्षण करने के उपरान्त ही शासन को उपलब्ध कराया जाय। स्पष्ट किया जाना है कि राजस्व पक्ष से पूँजी पक्ष तथा पूँजी पक्ष से राजस्व पक्ष में पुनर्विनियोजन प्रतिबन्धित है, अतः इस प्रकार के पुनर्विनियोग प्रस्ताव शासन को न उपलब्ध कराया जाय। यद्यपि यह अपेक्षा की जाती है कि सामान्यतः लेखानुदान के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

8— शासनादेश संख्या: 2031/XX-1/12-5(4)/2012 दिनांक 27 जुलाई, 2012 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

9— यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक:-यथोपरि।

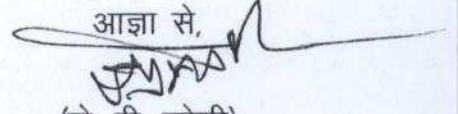
भवदीय,

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव

कमशः 3....

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
2. निदेशक कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव